National Election Watch

National Election Watch is the flagship programme of ADR which is a conglomeration of more than 1200 NGOs and social activists across India. Following activities are done as part of the program:

- Criminal, financial, educational and other background details of politicians are provided to citizens to help them make an informed choice while voting during elections.
- Extensive voter-awareness campaigns are run by the different State Chapters before and during Lok Sabha, Assembly and local body elections to curb the increasing influence of money and muscle power in politics. Voters are educated regarding the evils of not voting, vote selling, vote rigging etc. and encouraged to choose honest and credible candidates.
- Sources of income of political parties and their items of expenditure are analysed through the Income Tax returns filed by the parties with the IT department and presented to the public for greater transparency and accountability in the functioning political parties.
- The declared elections expenses of MPs & MLAs, Rajya Sabha MPs and performance details of MLAs and MPs prior to elections are also analysed with an aim to verify their claims and educate people about it.

What are your duties as a citizen of India

In a democracy, the role of a citizen is of utmost importance because citizens have the responsibility to choose their representatives for both State Assembly and Parliament. An informed and proactive citizenry which constantly questions the lawmakers, can compel the political parties not to field tainted candidates. MPs and performance details of MLAs and MPs prior to elections are also analysed with an aim to verify their claims and educate people about it.

- Exercise your franchise in every election and also encourage others to do the same.
- Be an informed voter and know the background details of your candidates and also share this information with others.
- Vote for credible and clean image candidates and ask others to do the same.
- If any candidate tries to buy your vote or threatens you, expose him/her and also report to the ECI.
- Use RTI as a medium to learn more about your candidate.
- Increase pressure on political parties to stop giving tickets to candidates with criminal background.
- Actively participate in voter awareness campaigns and other such activities to educate the citizens.
- Don't become party to spreading of fake news on social media.
- Check in newspapers & on political parties websites whether political parties have declared list of candidates with criminal cases & given reasons for allotting them tickets to contest elections (as directed by the Supreme Court).

What kind of election expenditure activities are illegal & criminal offences?

- Bribing voters with cash, alcohol and other gift items in order to buy their votes.
- Resorting to the practice of paid news or getting favourable news articles published in newspapers and news channels by paying money to the publishers.
- There is an election expenditure limit for both MPs and MLAs in every state. If any candidate spends more than the prescribed expenditure limit then it is an offence under law.
- It is a crime to publish a candidate's advertisement without his assent by a third party. If the candidate knows about this he must include it in his election expenditure declaration.
- As per law, it is mandatory to mention the name of the publisher/printer on the election hoardings, posters and banners.

What is **NOTA**

NOTA or 'None of the Above' option made its debut in the Electronic Voting Machine (EVMs) in 2013 in Chhattisgarh, Mizoram, Rajasthan and Madhya Pradesh and Delhi Assembly Elections. This option has provided the voters with a right to reject all the candidates contesting an Assembly or Lok Sabha polls if the voter feels none of the candidates are suitable enough.The total number of votes polled for NOTA option were 5, 42,295 (1.42%) votes during the Madhya Pradesh State Assembly Elections, 2018 and 3,40,984 (0.92%) votes during the Lok Sabha Election 2019 for 29 Parliamentary Constituencies of Madhya Pradesh.

Madhya Pradesh Lok Sabha 2019

Total MPs analyzed : 29

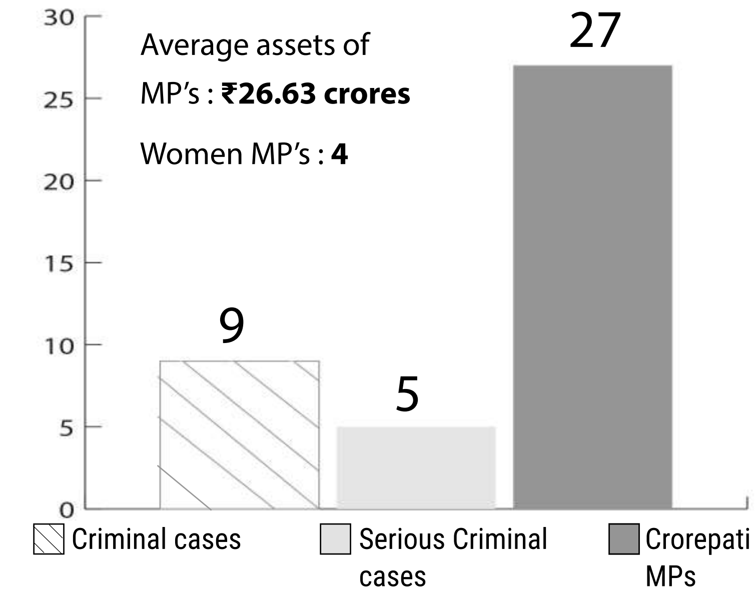

Madhya Pradesh Assembly Elections 2013

Total MLAs analyzed: 230

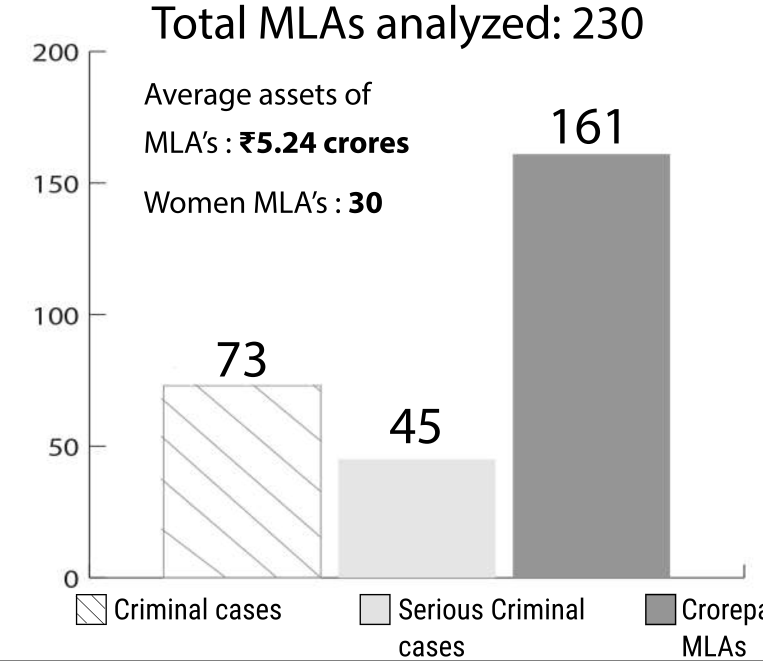

Madhya Pradesh Assembly Elections 2018

Total MLAs analyzed: 230

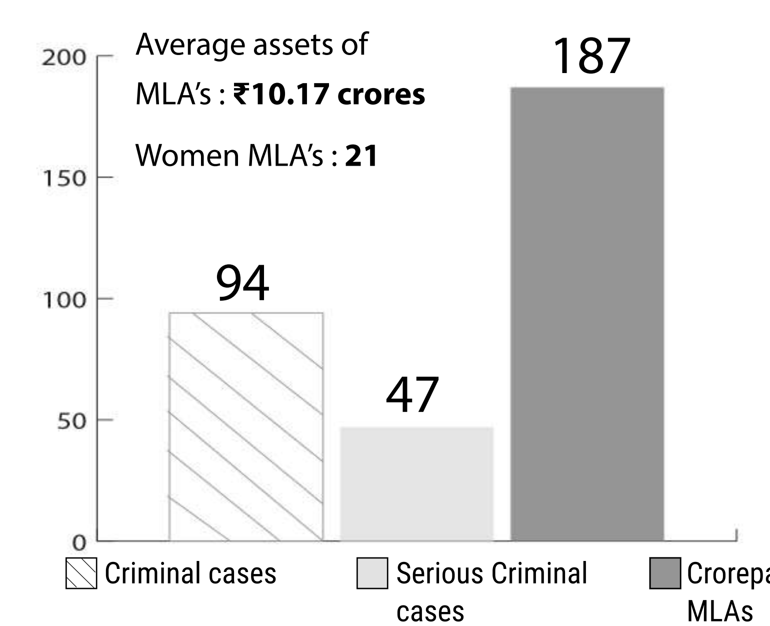

Madhya Pradesh 2018 Assembly Party-wise Criminal & Serious Criminal Cases

In Madhya Pradesh 2018 Assembly Polls, 47 MLAs had declared serious criminal cases like murder, attempt to murder, extortion, kidnap and robbery, against themselve. Party-wise details of the MLAs with serious criminalcases has been given in the Table below.

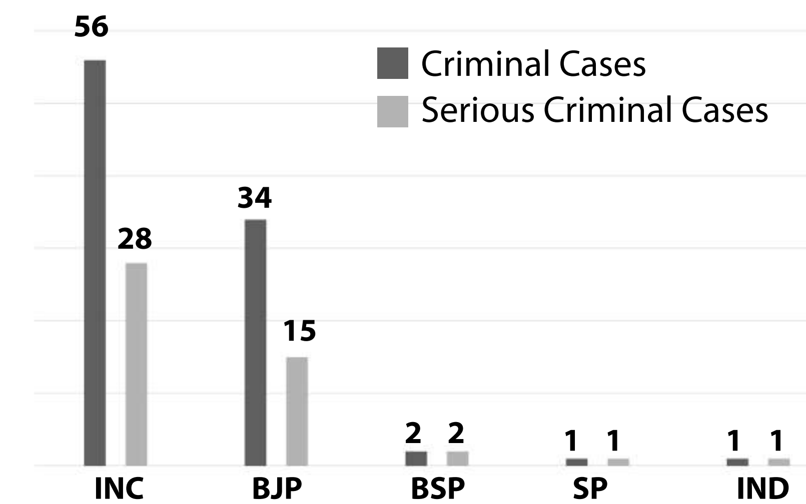

All India Income and Expenditure of Political Parties FY 2018-19, which won seats in Madhya Pradesh elections 2018

Party	Income	Expenditure
BJP	₹2410.08 Crores	₹1005.33 Crores
INC	₹918.03 Crores	₹469.92 Crores
BSP	₹69.79 Crores	₹48.88 Crores
SP	₹33.807 Crores	₹50.92 Crores
Total	₹3431.707 Crores	₹1575.05 Crores

Give us a missed call on: **08010445555** or
Call our Free Helpline No: **1-800-110-440**

For more details visit our websites: **www.myneta.info, www.adrindia.org**
Send SMS: **Myneta<PINCODE or CONSTITUENCY> to 56070 or 09212356070**

ADR Association for Democratic Reforms

myneta.info National Election Watch

नेशनल इलेक्शन वॉच क्या है? यह क्या करता है?

● यह देश में चुनाव–सुधारों के लिए कार्यरत 1200 से अधिक अराजनीतिक,निष्पक्ष गैर–सरकारी संगठनों का राष्ट्रव्यापी अभियान है।

● मतदाताओं को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देकर जागरुक बनाता है और इस प्रकार उन्हें सोच–समझकर फैसला करने में समर्थ बनाता है।

● लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान भ्रष्ट तरीकों के इस्तेमाल की निगरानी करने में नागरिक समाज के पहरेदार के रूप में काम करता है।

● राजनीतिक पार्टियों के कार्यकलापों और कोष–संग्रह में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व स्थापित करने की दिशा में कार्य करता है।

आपका लोकतंत्र.....आपकी भूमिका

किसी लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग नागरिक होते हैं क्योंकि उनपर संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधिओं को **चुनकर भेजने** की जिम्मेवारी होती है। स्व–सक्रिय जागरुक मतदाता लगातार जवाब मांगते हुए राजनीतिक पार्टियों को मजबूर कर सकता है कि वे चुनावों में ऐसे उम्मीदवारों को न उतारें जो मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धनबल व बाहुबल का इस्तेमाल करते हैं और अयोग्य हैं।

1. मतदान करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें।
2. आपके निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करें और दूसरों को भी इसे बताने का प्रयत्न करें।
3. चुनावों के दौरान अपने मत के बारे में सोच–समझकर फैसला करें।
4. स्वच्छ पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का समर्थन दें और प्रोत्साहित करें।
5. ऐसे उम्मीदवारों का विरोध करें जो मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करने के लिए अपने धनबल और प्रभाव का इस्तेमाल करता है।
6. अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से सवाल पूछने में सूचना के अधिकार जैसे माध्यमों का इस्तेमाल करें।
7. नागरिक समाज की गतिविधियों में सक्रियता के साथ हिस्सा लें और भागीदार बनें तथा उन लोगों के बीच जागरुकता भी फैलाएं जो इसके बारे में नहीं जानते।
8. राजनीतिक पार्टियों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को टिकेट नहीं देने के लिए मजबूर करें ।
9. फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया द्वारा फैलाये जाने वाली फेक न्यूज एवं गलत जानकारी को बिना विश्लेषण किये बढ़ावा न दें।
10. जांच करें की, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गए आदेश अनुसार सभी राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों का आपराधिक विवरण व टिकट देने के कारण का टीवी, अखबार, वेबसाइट एवं सोशल मीडिया पर 3 बार प्रचारित किया है या नही।

चुनावों के दौरान कौन–कौन से खर्च अवैध और आपराधिक हैं?

● मतदाताओं को शराब या नगद घूस देना या किसी दूसरे प्रकार से प्रभावित करना कानूनन अपराध है।

● पेड–न्यूज़: किसी समाचार संस्थान के किसी अधिकारी को किसी समाचार को प्रकाशित करने के एवज में भुगतान करना अपराध है।

● विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान किसी उम्मीदवार द्वारा रू. 28 लाख से अधिक खर्च करना कानूनन अपराध है। किसी भी राज्य के लिए लोक सभा व विधानसभा चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा भारतीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

● किसी उम्मीदवार के पक्ष में उसकी सहमति के बगैर किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा विज्ञापन दिया जाना कानूनन अपराध है और अगर उसकी सहमति से दिया जाए तो उसे चुनाव खर्च में शामिल किया जाएगा।

● चुनावी पोस्टर, होर्डिंग्स इत्यादि को मुद्रक के नाम के बगैर प्रकाशित करना अवैध है।

NOTA क्या है?

NOTA बटन ने 2013 में विधानसभा चुनाव में अपनी शुरूआत करी। आपके क्षेत्र में विधायक अथवा सांसद पद के लिए कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। यदि आपको लगता है कि इनमे से कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित होने योग्य नही है तो आप इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में **NOTA** बटन ''उपरोक्त में कोई नहीं'' का प्रयोग करके सभी उम्मीदवारों का बहिष्कार कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में नोटा बटन पर किए गए कुल मतदानों की संख्या 5,42,295 (1.42%) और मध्य प्रदेश लोक सभा चुनाव 2019 के 29 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में नोटा बटन पर किए गए कुल मतदानों की संख्या 3,40,984 (0.92%) थी।

मध्य प्रदेश लोकसभा 2019

कुल 29 सांसदों का विश्लेषण

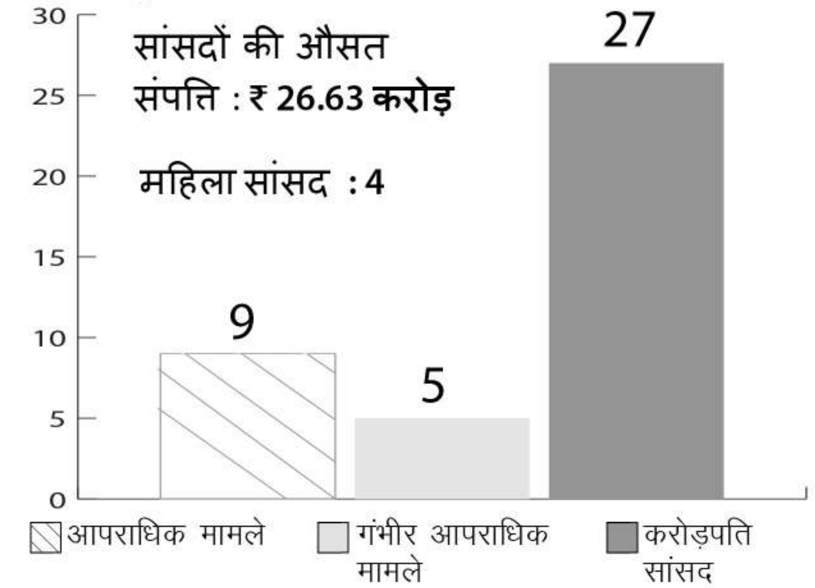

मध्य प्रदेश विधानसभा 2013

कुल 230 विधायकों का विश्लेषण

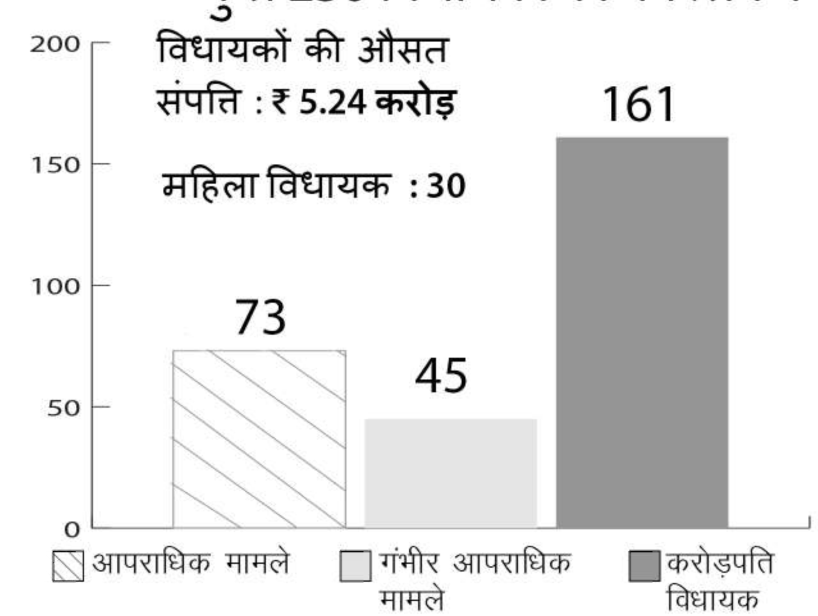

मध्य प्रदेश विधानसभा 2018

कुल 230 विधायकों का विश्लेषण

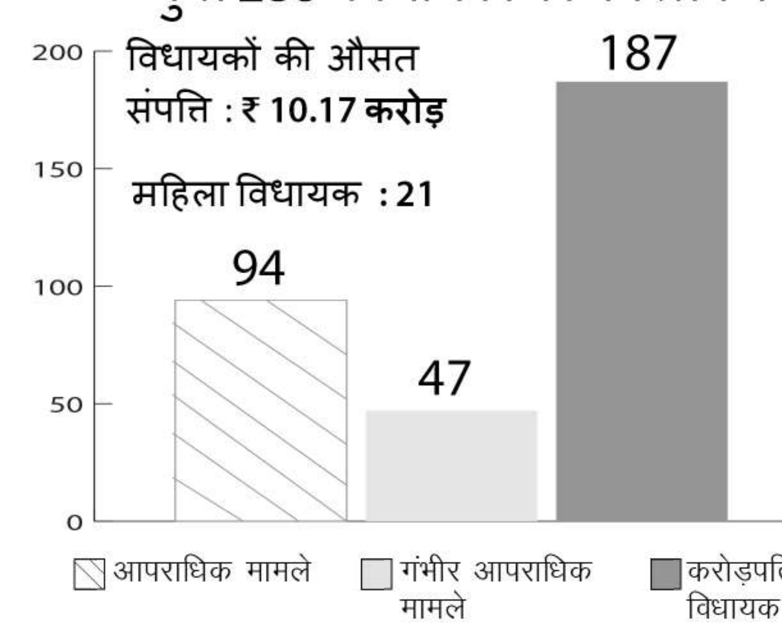

मध्य प्रदेश विधानसभा 2018 विधायकों के गंभीर आपराधिक मामले–दलवार

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में 94 विधायकों ने अपने पर आपराधिक मामले घोषित किये हैं इनमे 47 विधायकों ने अपने पर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किये हैं जैसे– हत्या, हत्या का प्रयास, ज़बरन वसूली, अपहरण, डकैती इत्यादि। नीचे की तालिका में आपराधिक मामले घोषित करने वाले विधायकों का दलवार आलेख दिया गया है

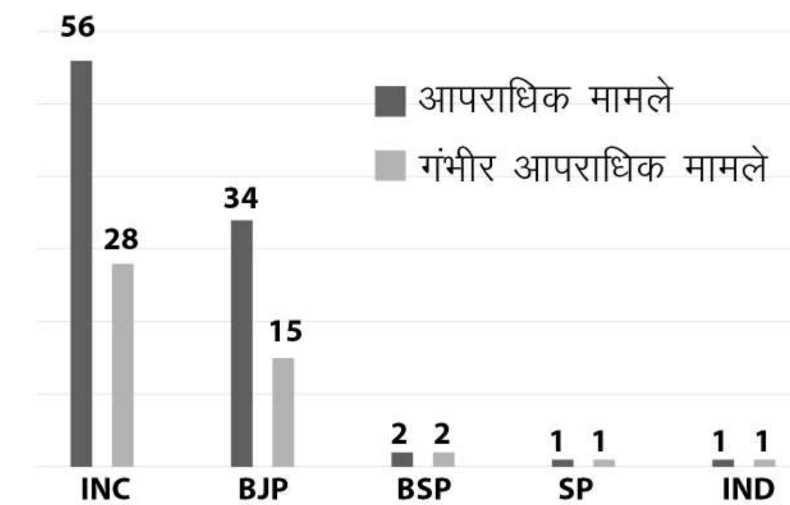

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में जीते हुए राजनीतिक दलों को पूरे भारतवर्ष से प्राप्त आय/व्यय का विवरण (वित्तीय वर्ष –2018–19)

दल	आय	व्यय
BJP	₹2410.08 करोड़	₹1005.33 करोड़
INC	₹918.03 करोड़	₹469.92 करोड़
BSP	₹69.79 करोड़	₹48.88 करोड़
SP	₹33.807 करोड़	₹50.92 करोड़
कुल योग	₹3431.707 करोड़	₹1575.05 करोड़

मिस्ड कॉल करें:
08010445555
टोल फ्री नंबर पर कॉल करें:
1-800-110-440

अधिक जानकारी के लिए, हमारी वेबसाइट पर विज़िट करें
www.myneta.info, www.adrindia.org
एसएमएस करें: **Myneta <PINCODE or CONSTITUENCY> to 56070 or 09212356070**

ADR Association for Democratic Reforms

myneta.info National Election Watch